प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कस्टोडियन बनकर करना होगाः शेखावत

संवाददाता

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का केन्द्रीय जल शक्ति ने किया शुभारंभ

नैनीताल। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में गुरुवार को ''सहभागी स्प्रिंग शेड प्रबन्धन के माध्यम से पहाड़ों में पीने योग्य पानी की व्यवस्था'' विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने दीप जलाकर किया। कार्यशाला में क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य, अपर सचिव केन्द्रीय अतिरिक्त सचिव भरत लाल, डीडीडब्ल्यूएस निदेशक रूपा मिश्रा, उत्तराखण्ड पेयजल सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी, प्रोफेसर डॉ. जेएस रावत मौजूद थे।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने जलवायु परिवर्तन एवं तापमान वृद्धि के दुष्परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन एवं तापमान वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कस्टोडियन बनकर करना होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना होगा। वर्तमान समय पानी की मांग लगातार बढ़ रही है परन्तु जल संसाधनों में कमी आ रही है। नया भारत बिना जल प्रबंधन के नहीं हो सकता है।

वर्षा से पानी पूर्व की तरह ही प्राप्त हो रहा है परंतु प्रबंधन में कमी आयी है। उन्होंने कहा कि नदियॉ, तालाब, झरने, सूखने लगे हैं और ग्राउण्ड वाटर लेवल भी गिर रहा है। इनका संरक्षण, संवर्धन एवं पुर्नजीवित करने के लिए कार्यों में गति बढ़ाकर कम समय में अधिक कार्य करने होंगे। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल को साझा करना, व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर चर्चा एवं निष्कर्स तथा अनुभवों के आधार पर स्प्रिंग शेड प्रबन्धन गतिविधियों के लिए जनता को जागरूक करना व हर घर में नल और हर नल में जल की संकल्पना को साकार करना है। शेखावत ने कहा कि पिछले 70 सालों में जितने घरों तक पेयजल की आपूर्ति की गयी, उसके सापेक्ष पॉच वर्षों (2019 से 2024 तक) के लिए लक्ष्य पॉच गुना बढ़ाकर देश के 15 करोड़ ग्रामीण आवासों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

राईजिंग स्टार्स ने मनाया कल्चरल फैस्ट किया समानित

संवाददाता हरिद्वार। ज्वालापुर की सुभाष नगर क्लोनी में स्थित दीक्षा राईजिंग स्टार्स पब्लिक स्कूल में नन्ने–मुन्ने बच्चों द्वारा कल्चरल फैस्ट 2020 का आयोजन किया गया। जिसमें कक्षा प्ले ग्रुप से यूकेजी कक्षा के बच्चों ने प्रतिभाग किया। जिसमें भारतीय सस्कृति, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण ही हमारा जीवन है आदि विषयों पर आधारित लघुनाटिका प्रस्तुत की गई एवं बच्चों ने अपनी नृत्य प्रतिभा से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपभोगता फोरम हरिद्वार की सदस्य अंजना चढ़ढा, विशाल गर्ग, किरन सिंह, हरेन्द्र मलिक निदेशक ग्लोबल पब्लिक स्कूल एवं बीएस रौतेला निदेशक ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, विरेन्द्र चढ़ढा, नीरज मंगल वरिष्ठ समाज सेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीक्षा राईजिंग स्टार्स पब्लिक स्कूल के संस्थापक जयप्रकाश अग्रवाल ने की।

Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

सरकार पारदर्शिता से विकास कार्य कर रही हैः मुख्यमंत्री

घोषणा

सीएम ने किया 1 अरब 13 करोड 42 लाख की 78 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

संवाददाता

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में 1 अरब 13 करोड 42 लाख की 78 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 48 करोड 52 लाख, 68 हजार की 24 योजनाओं का लोकार्पण व 64 करोड, 89 लाख, 43 हजार की 54 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने महानगर हल्द्वानी की आन्तरिक सडकों हेतु 20 करोड रूपये की घोषणा भी की।

समारोह में मुख्यमंत्री ने वर्ग–4, वर्ग–1ख काबिज काश्तकारों को पट्टे, दीनदयाल आवास, आयुष्मती योजना के कार्ड लाभार्थियों को मुख्य मंच से ज्वाला दत्त, विशना देवी, धीरेन्द्र कुमार, दयाकिशन, कमला देवी, देवकी देवी, चम्पा, दीपा देवी, पार्वती, बबली आदि को वितरित किये। मुख्यमंत्री जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता से विकास कार्य कर रही है। जिसका जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होने कहा जनहित में शीघ्रता से नीतिगत निर्णय लिये जायेंगे। उन्होने कहा कि कही भी पेयजल की कमी नही होने दी जायेगी।

विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए सीएम।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 500 विद्यालयों मे वर्चुअल क्लासेज प्रारम्भ कर दी है, 700 विद्यालयों मे भी जल्द ही वर्चुअल क्लासेज प्रारम्भ की जायेंगी। उन्होने कहा प्रत्येक संचालित आंगनबाडी केन्द्र का अपना भवन होगा। 2022 तक प्रत्येक सडक जिसमें पुल की जरूरत है पुल बनाये जायेंगे। गन्ना व धान की फसलों का बकाया भुगतान काश्तकारों को कर दिया गया है। साथ ही गेंहू का भुगतान काश्तकारों को चौबीस घंटे के भीतर भुगतान किया जायेगा। प्रदेश मे हैली सेवायें प्रारम्भ कर दी गई है। हल्द्वानी आईएसबीटी को सुन्दर व भव्य बनाया जायेगा। हल्द्वानी में 3.25 करोड का इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनने जा रहा है जो प्रदेश का प्रथम शवदाह गृह है, शवदाह के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।

भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। विकास कार्यो में केन्द्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होने कहा कि दशकों से जमरानी बांध परियोजना को सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान कर दी गई है, जिससे तराई व भाबर को नवजीवन मिलेगा। उन्होने कहा भूमिहीनों को पटटा दिलाने, युवाओं, महिलाओं को समूहों के माध्यम से रोजगार को जोडने का कार्य सरकार के नेतृत्व मे किया जा रहा है जो सराहनीय है।

हर घर में नल और हर नल में जल है उद्देश्य

संवाददाता

राज्य में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाले कार्यो की गहनता से हुई समीक्षा

नैनीताल। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत तथा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में राज्य में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाले कार्यो की गहनता से समीक्षा की। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि जल जीवन मिशन समयबद्ध कार्यक्रम है और इस कार्य को पूरा करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए रणनीति बनाकर कार्य करने को कहा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नदियों, तालाबों, गाड़–गधेरों, चाल–खाल एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2022 तक हर घर में नल और हर नल में जल की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्य के पूर्ण होने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेशभर के सभी तोकों, ग्रामों, ब्लॉकों, जनपदों तथा राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय अपर सचिव जल जीवन मिशन भरत लाल ने कहा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में नल और हर नल में जल है। उन्होंने कहा कि मिशन तभी सार्थक होगा, जब हर नल में पानी होगा। उन्होंने कहा कि हर नल में पानी के लिए जल स्रोतों को रिचार्ज करने की भी कार्य योजना तैयार करनी होगी। पेयजल की गुणवत्ता के लिए सेंसर भी लगाये जायेंगे जिनके माध्यम से पेयजल के 6 से 11 पैरा मीटरों की जॉच की जायेगी।

बैठक में पेयजल सचिव उत्तराखण्ड अरविन्द सिंह ह्यांकी ने हाउस हॉल्ड सर्वे, जेजेएम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, शिकायत निवारण सिस्टम, राज्य में जल संसाधन सिस्टम, ग्रामीण, जिला एवं राज्य कार्य योजना, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

स्वास्थ्य बिगड़ने पर धरना दे रहे राजेश शर्मा को अस्पताल में कराया भर्ती

संवाददाता देहरादून। शीशमबाड़ा कूड़ा निस्तारण केन्द्र के विरोध में धरना दे रहे आन्दोलनकारी राजेश शर्मा का स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने की वजह से पुलिस प्रशासन द्वारा 108 से दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस अवसर पर बताया गया कि राजेश शर्मा पिछले 60 दिनों से कूड़ा निस्तारण केन्द्र के विरोध में रात दिन धरना दे रहे थे और उन्होंने प्लांट के विरोध में 14 दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी। आज सुबह उनकी तबीयत बहुत खराब हो गयी जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा आपातकालीन सेवा 108 बुलाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहीं लंबे आन्दोलन और जनविरोध के बाद भी शासन प्रशासन कोई भी सुध नहीं ले रहा है जिससे क्षेत्रवासियों में खासा आक्रोश है और ना ही मानकों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे कूड़ा निस्तारण केन्द्र पर ही कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस अवसर पर ग्रामीणो ने आरोप लगाया कि कूड़े के निस्तारण की बजाए कूड़ा प्लांट के अंदर डंप किया जा रहा है जिसमें मरे हुए जानवर अस्पतालों का कचरा और भी कई तरह का खतरनाक कूड़ा प्लांट में लाया जा रहा है।

न्यूज डायरी

डायट के प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का धरना प्रदर्शन जारी

(संवाददाता) देहरादून। मिशन नियुक्ति अप्रैल 2020 के तहत अनिश्चितकालीन धरने के चौथे दिन भी राज्य के 13 जनपदों से राज्य सरकार के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा देहरादून में धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस अवसर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रशिक्षुओं द्वारा सर्वप्रथम निदेशालय परिसर में ही प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जिसका संचालन जनपद पिथौरागढ़ के प्रशिक्षितों द्वारा किया गया। डायट के प्रत्येक प्रशिक्षितों द्वारा शिक्षामंत्री को पत्र पेटी में पत्र एकत्रित कर प्रेषित किये गये एवं मॉग की गई कि विद्यालयों में नवाचारों को प्रोत्साहित करने हेतु डी.एल.एड. (बी.टी.सी.) प्रशिक्षितों की नियुक्ति अतिशीघ्र की जाए।

राज्य सरकार ने बेरोजगारों के साथ किया विश्वासघातः धस्माना

संवाददाता देहरादून। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित फारेस्ट भर्ती में हुए घोटाले, राज्य में शराब को बढ़ावा देने की नीति व महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाये जा रहे अभियान की कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आगामी एक मार्च रविवार को राजधानी देहरादून में गांधी पार्क में धरने के ऐलान किया है। यहां जारी एक बयान में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य की सरकार ने राज्य के बेरोजगारों के साथ विश्वासघात किया है। पिछले तीन वर्षों में किसी भी विभाग में बेरोजगारों की भर्ती करना तो दूर की कौड़ी रही उल्टा फारेस्ट गार्ड भर्ती में भारी घोटाला करने के लिए प्रवेश परीक्षा में ही पेपर लीक करवा दिया।

आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण न होना चिंताजनकः धीरेन्द्र

संवाददाता देहरादून। चिह्नित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के संरक्षक व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा है कि आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण न होना चिंताजनक है। आज परेड ग्राउंड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में समिति के तत्वावधान में लाचार, पंगु और निरीह किशोर उत्तराखंड विषय में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज आंदोलन कारियों के हितों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं किये गये है जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को छलने का काम किया जा रहा है और कांग्रस सरकार में जो चिह्नीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी उस पर इस सरकार ने विराम लगा दिया है।